

NOTICE

Caution to public against buying/dealing with assets of Sai Prasad Group of companies and its Directors

It is brought to the notice of the public at large that Hon'ble the Supreme Court of India vide order dated July 15, 2024, read with other orders passed from time to time, in Writ Petition (Crl.) No.546 of 2023 in the matter of Balasaheb Keshavrao Bhapkar & Ors. vs. Securities and Exchange Board of India has *inter alia* constituted a High-Powered Sale Committee (hereinafter referred to as "HPSC") and has empowered HPSC to liquidate all the movable and immovable assets of Sai Prasad Group of companies viz.

- (i) M/s. Sai Prasad Properties Ltd.,
- (ii) M/s. Sai Prasad Foods Ltd.,
- (iii) M/s. Sai Prasad Corporation Ltd. (hereinafter referred to as "SPG companies") and
- (iv) its directors viz., Shri Balasaheb Keshavrao Bhapkar, Smt. Vandana Bhapkar and Shri Shashank B. Bhapkar,

situated in various States by way of public auction, which are attached vide Notifications dated 23.03.2016 and 28.06.2016 by Government of Maharashtra under the Maharashtra Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 1999 (MPID Act) and vide Prohibitory Orders dated 10.03.2017 and 12.02.2020 in recovery proceedings initiated by Securities and Exchange Board of India (SEBI) under section 28A of the SEBI Act, 1992.

The HPSC has also been vested with all the powers of a civil court for taking necessary actions to speed up the liquidation of the properties of the SPG companies. Further, the Hon'ble Supreme Court has given directions that no court or authority can create a third party interest in the assets of SPG companies and its directors attached by Government of Maharashtra and SEBI.

In compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court, HPSC has started the process of sale of assets of SPG companies and its directors by way of public auction with the assistance of StockHolding Document Management System Ltd.

The public at large is cautioned against buying/dealing with any of the assets wherein the SPG companies or its Directors or any of its associates/subsidiaries have any interest/rights, directly or indirectly. Further, any person illegally and unauthorizedly buying or dealing with or taking possession of the assets of SPG companies or its Directors or any of its associates/subsidiaries shall be doing at his own risk and shall be liable for action in accordance with law since in terms

of the directions of the Hon'ble Supreme Court, power to auction/sell them lies solely and exclusively with the HPSC as these properties stand encumbered and are not free for being registered in favour of any third person / party.

Place: New Delhi
Date: June 10, 2025

MEMBER SECRETARY

सूचना

साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों की संपत्तियों को खरीदने / उनमें लेनदेन (डील) करने के संबंध में सावधानी बरतें

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि बालासाहेब केशवराव भापकर एवं अन्य बनाम सेबी से संबंधित रिट याचिका [(आपराधिक) - सं. 2023 की 546] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 जुलाई, 2024 को आदेश (समय-समय पर पारित किए गए अन्य आदेशों के साथ पठित) जारी करके एक उच्च स्तरीय बिक्री समिति (जिसका उल्लेख यहाँ आगे “एच.पी.एस.सी.”) भी गठित की और उसे साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज (जिसका उल्लेख यहाँ आगे “एसपीजी कंपनियों” के रूप में किया गया है - जो निम्नलिखित कंपनियों के नाम से रजिस्टर हैं) की समस्त चल और अचल संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी के जरिए बिक्री करने का कार्य दिया:

- (i) मैसर्स साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लि.,
- (ii) मैसर्स साई प्रसाद फूड्स लि.,
- (iii) मैसर्स साई प्रसाद कारपोरेशन लि., और
- (iv) उनके निदेशक (अर्थात् श्री बालासाहेब केशवराव भापकर, श्रीमती वंदना भापकर और श्री शशांक बी. भापकर)

ये संपत्तियाँ अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं और जिनकी कुर्की महाराष्ट्र जमाकर्ताओं (वित्तीय संस्थानों में) के हितों का संरक्षण अधिनियम, 1999 (एमपीआईडी एक्ट, 1999) के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा 23.03.2016 और 28.06.2016 की अधिसूचना के माध्यम से और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) की धारा 28क (28ए) के तहत शुरू की गई वसूली कार्यवाहियों के तहत तारीख 10.03.2017 और 12.02.2020 को जारी किए गए प्रतिषेधात्मक आदेशों (प्रोहीबिटरी आर्डर) के माध्यम से की गई हैं।

एच.पी.एस.सी. को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ सौंप दी गई हैं, ताकि वह एसपीजी कंपनियों की संपत्तियों की बिक्री आदि की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए हर जरूरी कदम उठा सके। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निदेश भी दिए हैं कि कोई भी न्यायालय या प्राधिकरण यह पक्ष नहीं रख सकता कि एसपीजी कंपनियों और उनके निदेशकों की संपत्तियों [जिनकी कुर्की महाराष्ट्र सरकार और सेबी द्वारा की गई हैं] में किसी भी दूसरे व्यक्ति आदि का कोई हित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों का पालन करते हुए, एच.पी.एस.सी. ने स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम लि. के सहयोग से सार्वजनिक नीलामी के जरिए एसपीजी कंपनियों और उनके निदेशकों की संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे उन संपत्तियों को न तो खरीदें और न ही उनमें कोई लेनदेन करें, जिनमें एसपीजी कंपनियों अथवा उनके निदेशकों या उनके किन्हीं सहयोगियों (असोसिएट्स) / सहायक कंपनियों (सब्सिडियरीज़) का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित / अधिकार हो। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति एसपीजी कंपनियों अथवा उनके निदेशकों या उनके किन्हीं सहयोगियों (असोसिएट्स) / सहायक कंपनियों (सब्सिडियरीज़) की संपत्तियों को गैर-कानूनी तथा अनधिकृत तरीके से खरीदेगा या उनमें कोई लेनदेन करेगा या उनका कब्ज़ा अपने हाथों में लेगा, तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा और साथ ही उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार उन संपत्तियों की नीलामी / बिक्री करने का अधिकार पूरी तरह से एच.पी.एस.सी. के ही पास है और इन संपत्तियों पर एन्कंब्रेंस भी है तथा इनकी रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति / पक्ष के नाम पर भी नहीं की जा सकती।

स्थान : नई दिल्ली

सदस्य सचिव

तारीख: 10 जून, 2025

सूचना

साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि त्यांच्या संचालकांच्या मालमत्ता खरेदी / व्यवहार (डील)
करताना खबरदारी घ्यावी.

सर्वसामान्य जनतेस सूचित करण्यात येते की, बालासाहेब केशवराव भापकर आणि इतर विरुद्ध सेबी यासंदर्भातील [(आपराधिक) रिट याचिका क्र. 546/2023] प्रकरणात, मा. सर्वोच्च

न्यायालयाने दिनांक 15 जुलै 2024 रोजी (वेळोवेळी पारित केलेल्या इतर आदेशांसह वाचावे) एक आदेश काढून एक उच्चस्तरीय विक्री समिती (यास पुढे “एच.पी.एस.सी.” असे संबोधले आहे) गठीत केली असून तिला साई प्रसाद गुप ऑफ कंपनीज (पुढे “एसपीजी कंपन्या” म्हणून ओळखले जाईल - खालील कंपन्यांनुसार नोंदणीकृत) यांच्या सर्व अचल व चल मालमत्ता सार्वजनिक लिलावामार्फत विक्री करण्याचे कार्य सोपविले आहे:

- (i) मैसर्स साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लि.,
- (ii) मैसर्स साई प्रसाद फूड्स लि.
- (iii) मैसर्स साई प्रसाद कॉर्पोरेशन लि., आणि
- (iv) वरील कंपन्यांचे संचालक (श्री. बालासाहेब केशवराव भापकर, श्रीमती वंदना भापकर व श्री. शशांक बी. भापकर)

ही मालमत्ता विविध राज्यांमध्ये स्थित असून त्यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण अधिनियम, 1999 (एमपीआयडी ॲक्ट, 1999) अंतर्गत दिनांक 23.03.2016 आणि 28.06.2016 रोजी काढलेल्या अधिसूचनांद्वारे तसेच भारतीय सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी ॲक्ट, 1992) च्या कलम 28क (28A) अंतर्गत 10.03.2017 आणि 12.02.2020 रोजी काढण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांद्वारे जप्ती लावण्यात आलेली आहे.

एच.पी.एस.सी. ला सिव्हिल न्यायालयाचे सर्व अधिकार देण्यात आले असून, त्यांनी एसपीजी कंपन्यांच्या मालमत्तांच्या विक्री प्रक्रियेस गती देण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलावीत असे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेश दिला आहे की, कोणतेही न्यायालय किंवा प्राधिकरण हे म्हणू शक्त नाही की जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांवर (ज्यांच्यावर महाराष्ट्र शासन व सेबीने जप्ती लावलेली आहे) कोणत्याही तृतीय पक्षाचा हितसंबंध आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशांचे पालन करून, एच.पी.एस.सी. ने स्टॉक होल्डिंग डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम लि. यांच्या सहकार्याने सार्वजनिक लिलावाद्वारे एसपीजी कंपन्या व त्यांच्या संचालकांच्या मालमत्तांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

सर्वसामान्य जनतेस इशारा दिला जातो की त्यांनी अशा मालमत्तांची खरेदी करू नये वा त्यांच्यात कोणताही व्यवहार करू नये - ज्या मालमत्तांमध्ये एसपीजी कंपन्या, त्यांचे संचालक वा त्यांचे कोणतेही सहयोगी / सहाय्यक कंपन्या यांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष हितसंबंध/अधिकार आहे.

याव्यतिरिक्त, कोणतीही व्यक्ती जर अशा मालमत्तांची बेकायदेशीर व अनधिकृत खरेदी करते, त्यांच्यात व्यवहार करते वा त्यांचा ताबा घेतो, तर त्यासाठी ती व्यक्ती स्वतः जबाबदार असेल आणि तिच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, अशा मालमत्तांच्या लिलाव / विक्रीचा पूर्ण अधिकार फक्त एच.पी.एस.सी. कडेच असून त्या मालमत्तांवर आधीपासून अडथळे (encumbrances) आहेत आणि त्या कुठल्याही तृतीय पक्षाच्या नावे नोंदवता येणार नाहीत.

सदस्य सचिव

स्थळ: नवी दिल्ली

दिनांक: 10 जून 2025